पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 23, अंक 3/2022

शहरी सुशासन के लिए योजनाओं में नवाचार आवश्यक-विशेषज्ञ

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी 'कट्स' जयपुर द्वारा आस्ट्रेलियन हाईकमीशन के सहयोग से स्वायत्त शासन विभाग के तत्वाधान में 02 सितम्बर, 2022 को निदेशालय परिसर में शहरी निकायों के क्षमतावर्धन एवं बेहतर कार्यों को गति देने के लिए 'कट्स' एवं स्वायत्त शासन विभाग के मध्य सहमति प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

इस अवसर पर स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हिदेश कुमार शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वायत्त शासन निकायों का क्षमतावर्धन बहुत जरूरी है। सभी निकायों में बजट की भारी कमी रहती है। इस कमी को दूर करने के लिए रचनात्मक तरीकों से नवाचार अपनाकर राजस्व को बढ़ाया जा सकता है तथा शहरी सुशासन प्रणाली को बेहतर बनाया जा सकता है।

परिचर्चा में 'कट्स' के निदेशक जार्ज चेरियन ने कहा कि महात्मा गांधी ने भारत के ग्रामों में लोगों के निवास करने की बात कही थी। बढ़ते शहरीकरण के प्रभाव से आज ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। करीब 24 प्रतिशत लोग प्रति वर्ष शहरों की ओर पलायन करते हैं।

उन्होंने बताया कि भारत के बाहर के देशों में शहरी निकायों के महापौर को बहुत अधिक शक्तियां और अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन यहां शहरी निकायों में कार्यरत संस्थाओं के पास वित्तीय व्यवस्था एवं बजट नहीं होने से बहुत से विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। परिचर्चा के प्रारंभ में 'कट्स' के अमरदीप सिंह ने स्वागत उद्‌बोधन में बताया कि 'कट्स' द्वारा स्वायत्त शासन विभाग के साथ मिलकर आगामी दिनों में राजस्थान में शहरी निकायों के लिए जिलों में क्षमतावर्धन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि शहरी सुशासन प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके।

इस अवसर पर हैदराबाद महानगरपालिका के पूर्व अधीक्षण अभियंता डॉ. डी. सुधाकर ने कहा कि शहरी निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों को नवाचार के तरीके अपनाकर एवं जन भागीदारों से संवाद करके राजस्व में बढ़ोतरी करनी चाहिए। ऐसे बहुत से मामले हैं जहां पर शहरी निकायों के निवासी एवं वाणिज्यिक गतिविधि करने वाले भागीदार वर्षों से पुरानी दर से बहुत ही न्यूनतम गृहकर दे रहे हैं, जबकि वे वर्तमान समय में हो रहे विकास कार्यों का उपयोग कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यदि इन्हीं सभी भागीदारों को आपसी नवाचार के तरीके से संवाद करके बताया जाए तो वे कर की दरों को स्वेच्छा से बढ़ा कर दे सकते हैं। इसके साथ ही शहरी निकायों की उन्नति के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। उन्होंने हैदराबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां जन भागीदारी से 'सेल्फ असेस्मेंट' स्कीम के तहत काफी अच्छा राजस्व एकत्रित हुआ है जिसका शहरी विकास की गतिविधियों में अच्छा उपयोग हो रहा है।

परिचर्चा के दौरान स्वच्छ भारत मिशन टीम के सदस्यों ने सुझाव दिया कि स्वास्थ्य और स्वच्छता एवं ठोस कचरे का स्थाई समाधान बहुत जरूरी है। स्वायत्त शासन विभाग के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने कहा कि स्ट्रीट लाइटों के बारे में जनता को जागरूक किया जाना आवश्यक है। पर्यावरण विंग की अभियंता काव्या ने कहा कि स्वच्छता कार्यक्रम के तहत सफाई मित्रों की नियुक्ति करनी चाहिए।

नागरिक विकास समिति महासंघ के भूपराम शर्मा ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग की सभी योजनाओं में रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी को शामिल करना चाहिए। इसी तरह डा.सीमा जोशी, बाल आयोग के पूर्व सदस्य ने बताया कि शहरों की प्लानिंग चाइल्ड फ्रेण्डली होनी चाहिए।

स्वायत्त शासन विभाग की डॉ. हिमानी तिवारी नें कहा कि आगामी दिनों में 'कट्स' के द्वारा शहरी निकायों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, उनमें विभाग का पूरा सहयोग रहेगा। कार्यक्रम के अंत में 'कट्स' के अमित बाबू ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस अंक में...

- कृषि कनेक्शन टर्नकी प्रोजेक्ट में गोलमाल ... 3
- एसीबी भ्रष्ट 'मछलियों' को पकड़ने का कांटा 7
- बिजली मीटर सही, गणना हो रही गलत 8
- बीसलपुर से व्यर्थ बह गया पानी 9
- पेड़ों को काटे बगैर बन सकते हैं समृद्ध 10

'कट्स' की याचिका पर एनजीटी का फैसला

ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए राज्य सरकार को सख्त निर्देश

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राज्य सरकार को वाहनों के हॉर्न से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने व नियमों की पालना करने के आदेश दिए हैं। एनजीटी ने कहा है कि वाहन निर्माता को बिक्री के स्थान और तकनीकी प्रचार सामग्री में वाहनों के ध्वनि स्तर के बारे में जानकारी देनी होगी। उन्हें ध्वनि के स्तर को अपनी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करना होगा। जनता चैन से सो सके, इसके लिए एनजीटी ने प्रदेश में आवासीय क्षेत्रों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक नो हॉन्किंग जोन रखने के निर्देश भी दिए हैं।

इसके अतिरिक्त अनावश्यक हॉर्न बजाने वालों को 5,000 रुपए से दंडित कर उक्त राशि एक कोष में डाली जाने व उस अपराध की पुनरावृत्ति पर अपराधी से 10,000 रुपए की राशि दण्ड स्वरूप वसूलने और हॉर्न बजाने के उपकरण को जब्त करने का भी निर्देश दिया है।

ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए 'कट्स' की याचिका पर फैसला देते हुए एनजीटी ने 'कट्स' को इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा है, जिससे स्थानीय प्रशासन के साथ वेलफेयर एसोसिएशन सोसायटीज व समाजिक संगठनों को शामिल करने को कहा है।

एनजीटी भोपाल की बेंच में 'कट्स' के अधिवक्ताओं ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में शांतिपूर्वक जीने का अधिकार शामिल है। किसी भी तरह की तेज आवाज जिससे व्यक्ति की शांति व आराम में बाधा पहुंचे, यह अधिकारों का हनन है। याचिका में ध्वनि प्रदूषण रोकने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी के पूर्व फैसलों की पालना करवाने की गुहार की।

विशेषज्ञों द्वारा पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर अनिवार्य प्रभावी चेतावनी की मांग

'कट्स' इंटरनेशनल द्वारा 30 अगस्त, 2022 को जयपुर में 'उपभोक्ताओं में गैर संचारित रोगों को रोकने में एफ.ओ.पी.एल की भूमिका' विषयक परिचर्चा आयोजित की गई। परिचर्चा के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों एवं उपभोक्ता संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर अनिवार्य रूप से प्रभावी चेतावनी लेबल लगाए जाने के लिए खाद्य नियामक द्वारा जल्द से जल्द अधिसूचना जारी किए जाने की मांग की है। परिचर्चा में खासतौर पर यह उभर कर सामने आया कि किस प्रकार से हमारे खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं।

परिचर्चा में खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुनिल शर्मा ने कहा कि इस विषय पर अभी तक जानकारी और जागरूकता का अभाव है। इसको लेकर विभागीय स्तर पर गहन चर्चा की जाएगी और राष्ट्रीय स्तर पर पैरवी कर पैक्ड खाद्य पदार्थों पर प्रभावी चेतावनी लेबल को लागू करवाने का प्रयास किया जाएगा।

कार्यक्रम के प्रारंभ में 'कट्स' के निदेशक एवं एफएसएसएआई के केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य जॉर्ज चेरियन ने कहा कि फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग का उद्देश्य उपभोक्ताओं की मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। इससे चीनी, नमक और वसा जैसे अस्वास्थ्यकर अवयवों वाले उत्पादों को आसानी से पहचानने में मदद मिलेगी। जे.के.लॉन अस्पताल के प्रोफेसर एवं अधीक्षक डॉ. अशोक गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान एन.सी.डी. मामलों में रेड जोन में है और यही वह समय है जब हमें सचेत होकर बीमारियों के वास्तविक कारणों को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सही खाने की आदतों से मौतों की संख्या कम हो सकती है। परिचर्चा में ग्लोबल हेल्थ एडवोकेसी इंक्यूबेटर के राष्ट्रीय सलाहकार संजय पांडे ने चेतावनी लेबल के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह गैर संचारित रोगों के समाधान में सही कदम सिद्ध होगा।

मृतकों के नाम पर बांटा राशन का गेहूं

क्या मुर्दे भी गेहूं खाते हैं? प्रदेश की राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पिछले दो सालों में 1.85 लाख मृतकों के नाम पर 88.80 करोड़ रुपए का करीब 44 हजार टन गेहूं बांट दिया गया। इसका खुलासा राशन कार्ड और आधार की जांच में किया गया। यह 44,404 टन गेहूं कोरोना काल के दो साल में बांटा गया है। केंद्र सरकार ने एमएसपी की दर पर औसतन 20 रुपए किलो के हिसाब से यह गेहूं खरीदा। इसी गेहूं को गरीबों को 2 रुपए किलो के हिसाब से बांटा गया।

कोरोना काल में मुफ्त राशन स्कीम के तहत वर्ष 2021-22 में 11 हजार टन से अधिक गेहूं तो निःशुल्क ही बांट दिया गया। जिसकी खरीद करीब 22.20 करोड़ रुपए थी। परिवार के किसी सदस्य की मौत पर राशन कार्ड से नाम हटवाने की जिम्मेदारी कार्ड धारक की है। साथ ही मृतकों के नाम पर गेहूं आवंटित होना रसद विभाग के अफसरों पर भी सवाल खड़े करता है।

(दै.भा.,01.08.22)

छीन रहे बच्चियों के हक का कन्यादान

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। योजना की नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और ई-मित्र संचालकों ने मिलकर कन्यादान के लाखों रुपए हड़प लिए। इसका खुलासा तब हुआ, जब लाभार्थियों की राशि उनकी बजाय ई-मित्र संचालकों के खाते में जमा पाई गई।

जैसलमेर में 288 मामलों में जांच जारी है। जिले में करीब 1.30 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात सामने आई है। इसके बाद प्रदेशभर में मामले चिन्हित कर जांच की जा रही है। गौरतलब है कि योजना में सरकार निराश्रित, निर्धन, आरक्षित व अल्पसंख्यक वर्ग की कन्याओं की शादी में कन्यादान के रूप में आर्थिक सहायता देती है। *(दै.भा., 06.07.22)*

गरीबों के हक को डकार गए जिम्मेदार

श्रीगंगानगर सूरतगढ़ में 31 राशन डिपो से 1739 क्विंटल गेहूं गायब हो गया। यह गेहूं गरीबों को बांटा जाना था। इस पर जिला कलेक्टर रुक्मणि रियार सिहाग ने कार्यवाहक डीएसओ सुरेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार को दो बार पत्र भी लिख दिए , लेकिन उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई। इस पूरे घोटाले की जांच करने वाले तीनों रसद इंस्पेक्टरों को सरकार ने एकाएक हटा दिया। इस कार्रवाई के बाद सरकार की मंशा पर सवाल उठने शुरू हो गए।

जिला कलेक्टर सिहाग ने बताया कि दो बार हुई जांच में 1739.83 क्विंटल गेहूं और 4.24 क्विंटल चीनी की गड़बड़ी सामने आई। जिनमें कार्यवाहक डीएसओ सुरेश कुमार को नियम विरुद्ध निशुल्क गेहूं का उठाव करवाने के लिए जिम्मेदार माना गया। *(दै.भा., 04.09.22)*

कृषि कनेक्शन टर्नकी प्रोजेक्ट में गोलमाल

प्रदेश के किसानों को खेती के लिए 1.04 लाख बिजली कनेक्शन देने के टर्नकी प्रोजेक्ट में 1600 करोड़ रुपए का गोलमाल हो रहा है। जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को पूरी करने के लिए 2300 करोड़ रुपए के टेंडर लगाए, लेकिन निविदा की शर्तों में छह बार संशोधन कर दूसरे राज्यों की कई बड़ी कंपनियों को बाहर कर दिया और अफसरों की मिलीभगत कर ज्यादा दरों पर वर्कआर्डर दिया जा रहा है।

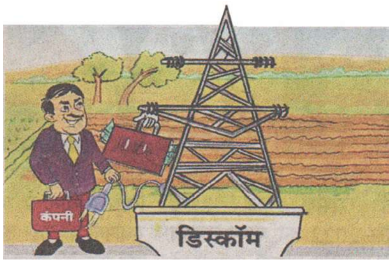

आरोप है कि इसी तरह पुलिंग व निविदा संशोधन हुई तो डिस्कॉम को 6400 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होगा। भविष्य में यह खर्चा टैरिफ बढ़ाकर आम उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा। टेंडरों में किए जा रहे गोलमाल की डिस्कॉम कांट्रेक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा डिस्कॉम चेयरमैन भास्कर ए. सावंत को विरोध भी किया गया है।

(दै.भा., 18.07.22)

बिना निगरानी पौधारोपण पर करोड़ों खर्च

प्रदेश की राजधानी में ही मानसून के दौरान पौधारोपण के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। लेकिन निगरानी तंत्र नहीं होने से जिम्मेदारों को ये पता ही नहीं कि कितने पौधे रोपे गए और उनमें से कितने पौधे जीवित है। लोगों का कहना है कि यदि निगरानी तंत्र मजबूत होता तो पांच साल में जयपुर ग्रीन सिटी बन जाता।

इस मानसून में दोनों नगर निगम एक लाख से भी ज्यादा पौधे वितरित कर रहा है। वहीं, जेडीए भी 60 हजार पौधे अपने खर्चे पर लगा रहा है। राजस्थान आवासन मंडल भी शहर में 18 हजार पौधे लगा रहा है। जेडीए के अनुसार पौधा खरीद की दर औसतन 150 रुपए से लेकर 500 रुपए है। लेकिन कितने पौधे रोपे गए और उनमें से कितने जीवित रहे इसका अधिकारियों के पास कोई हिसाब नहीं होता। जिम्मेदार अधिकारी पौधों की देखरेख का केवल शपथ पत्र लेकर इतिश्री कर लेते हैं। दरअसल, निगरानी तंत्र के नहीं होने से इन पौधों की सही देखरेख नहीं हो पाती। *(रा.प., 13.08.22)*

महिलाओं ने सरकार को दिखाया आईना

राज्य सरकार उड़ान योजना के तहत महिलाओं व किशोरियों को निःशुल्क सैनेटरी नैपकिन दे रही है। हाल ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इसके लिए 600 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। इससे प्रदेश में एक करोड़ 45 लाख किशोरियों व महिलाओं को नैपकिन उपलब्ध करवाएं जाएंगे। लेकिन अभी भी योजना कागजों तक ही है, सार्वजनिक स्थानों पर नैपकिन आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं।

इसके लिए अब खुद महिलाएं मुखर हुई हैं। उनका कहना है कि सरकार की उड़ान योजना कागजी साबित हो रही है। हकीकत यह है कि राजधानी में ही सार्वजनिक स्थानों पर सैनेटरी नैपकिन नहीं मिल रहे हैं तो गांव-ढाणियों की स्थिति क्या होगी, यह हम सोच सकते हैं। इसके अलावा जो नैपकिन दिए जा रहे हैं वह छोटे हैं और उपयोग में लिए जाने लायक नहीं हैं।

(रा.प., 06.09.22)

वेतन भत्तों के मामले में प्रदेश के विधायकों के ठाठ

वेतन भत्तों के मामले में राजस्थान के विधायकों के ठाठ हैं। उन्हें प्रति माह वेतन और निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में एक लाख दस हजार रुपए मिल रहे हैं। यदि सभी तरह के भत्तों को जोड़ दिया जाए तो वर्तमान में राजस्थान के विधायकों को करीब 2 लाख 37 हजार 500 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। प्रदेश में वर्ष 2019 में आखिरी बार विधायकों का वेतन बढ़ाया गया था, जिसका सदन में किसी ने भी विरोध नहीं किया था।

नियमों के तहत तो विधायकों का विधान सभा और सांसदों का संसद में वेतन भत्ते बढ़ाने का स्वयं ही निर्णय करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सैद्धान्तिक व नैतिक रूप से स्वयं के मामले में स्वयं ही निर्णय लेना ठीक नहीं है। इन्हें मिलने वाली अन्य सुविधाओं की गणना की जाए तो वेतन भत्ते की राशि काफी अधिक होगी। उचित यह है कि इनके वेतन भत्ते बढ़ाने का निर्णय किसी कमेटी की सिफारिश पर किया जाए, जिसमें विषय विशेषज्ञ शामिल हों। *(रा.प., 06.07.22)*

बेहतर काम के बावजूद नहीं मिला पैसा

केंद्र ने स्कूली बच्चों के दोपहर के भोजन, गरीबों के आवास निर्माण, आपदा राहत सहित आमजन से जुड़ी विभिन्न योजनाओं में 6677 करोड़ रुपए से अधिक की हिस्सा राशि अटका दी है। इसमें 2763 करोड़ रुपए तो पिछले साल के बकाया है। चालू वित्तीय वर्ष में 19 स्कीम के तहत 3913 करोड़ रुपए शामिल है, जो पहली तिमाही के बाद भी अब तक नहीं मिले हैं।

राज्य का दावा है कि केंद्र की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हुआ है, फिर भी राशि नहीं मिल रही। इससे राज्य में इन योजनाओं के आशार्थियों पर असर पड़ने की आशंका खड़ी हो रही है। प्रदेश की मुख्य सचिव उषा शर्मा का कहना है कि योजनाओं के अच्छे क्रियान्वयन के बावजूद फंड नहीं मिलना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सभी सचिव व्यक्तिगत तौर पर संबंधित केंद्रीय सचिवों से मिल कर फंड जारी करवाएं। *(दै.भा., 23.07.22)*

खून के बेशर्म कारोबारी कर रहे मिलावट

प्रदेश में रक्तदान को महादान मानकर लोग बढ़-चढ़कर इस पुण्य कार्य में शामिल होते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोगों के इस विश्वास को तोड़ने और शर्मसार करने वाला खून का काला कारोबार सामने आया है। यहां दान में मिले खून में सेलाइन वाटर मिलाकर उसकी मात्रा बढ़ाने और दोगुने दाम में बेचने का खुलासा एसटीएफ और ड्रग विभाग ने किया है।

चौंकाने वाली बात यह है कि एक बार फिर खून के इस काले कारोबार के तार राजस्थान के ब्लड बैंकों से भी जुड़े हैं। कारोबारी जयपुर, सीकर और चौमूं के 8 विभिन्न ब्लड बैंकों से रक्त ले जाकर यह कारोबार कर रहे हैं। छापेमारी में राजस्थान से तस्करी कर लाया गया 302 यूनिट घटिया मानव रक्त बरामद किया गया। गिरोह का नेटवर्क सात राज्यों में फैला है। *(रा.प., 02.07.22)*

फर्जी दस्तावेज से फसल बीमा घोटाला

बीकानेर जिले के महाजन क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ-2022 में फर्जी दस्तावेज लगाकर बीमा कराने व लाखों रुपए का बीमा क्लेम उठाने के मामले का गड़बड़झाला सामने आया है। एक ही कृषि भूमि का फर्जी ठेकानामा तैयार कर क्षेत्र के कुछ शातिर लोगों ने बड़ी क्लेम राशि उठाई है। बीमा कंपनी भी मुकदमा दर्ज कराने व फर्जी तरीके से उठाए क्लेम को वापस वसूलने की तैयारी में है।

इस साल 1 जुलाई से 1 अगस्त तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल का बीमा किसानों ने सीएससी के माध्यम से करवाया। रामबाग के एक व्यक्ति ने अर्जुनसर पटवार हलके के चक भंवरिया स्थित 800 बीघा कृषि भूमि का ठेकानामा दिखाकर अपने नाम से बीमा काट दिया। प्रीमियम राशि भी ऑनलाइन जमा करा दी। इसके बाद फर्जी दस्तावेज से बीमा क्लेम उठा लिया। मामले की अभी जांच चल रही है। *(रा.प., 15.08.22)*

अफसरों की सुस्ती से धुंधलाई आस

राज्य में करीब 50 लाख रोजगार देने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों (एमएसएमई) के लिए सरकार भले ही कई बड़ी नीति और कार्यक्रम लेकर आई हो, लेकिन अफसरों की कार्यशैली से इन उद्योगों को प्रोत्साहन की आस धुंधली पड़ रही है। इसी के चलते प्रदेश में जोर-शोर से शुरू हुए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (एमएलयूपीवाय) मिशन निर्यातक बनों जैसे कार्यक्रम लेटलतीफी का नमूना बन कर रह गया है।

सरकार ने इस योजना के जरिए अधिकाधिक औद्योगिक निवेश लाने की मंशा से ब्याज सब्सिडी पेटे मौजूदा वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रावधान रखा था। लेकिन अफसर इस मंशा के अनुरूप काम ही नहीं कर पाए। नतीजा यह हुआ आधा साल बीतने के बाद भी उद्योग विभाग सिर्फ 40 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे पाया है। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने भी इस पर नाराजगी जताई है और अफसरों को निर्देश दिए हैं। *(रा.प., 17.09.22)*

रोज खाई 25 लाख की दवाई

चिकित्सक, मेडिकल स्टोर संचालक, कर्मचारियों एवं पेंशनर ने मिलकर मुफ्त का चंदन इस कदर घिसा कि बिना मर्ज के ही सरकार को कर्ज की ओर धकेल दिया। भरतपुर जिले में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर परिवार प्रतिदिन करीब 25 लाख रुपए की दवा खा रहे हैं। आरजीएचएस के नाम पर दवा की जगह घरेलू सामान खरीदने की जानकारी के बाद सरकार ने अब मेडिकल स्टोर संचालकों का भुगतान रोक दिया है।

सतर्कता टीम ने कुछ ऐसे भी कर्मचारियों को चिन्हित किया है जो एक माह में एक-एक लाख रुपए की दवा ले रहे हैं। कुछ निजी अस्पताल संचालक और सरकारी चिकित्सक भी इस बंदरबाट में शामिल है। कर्मचारी और पेंशनर व मेडिकल स्टोर की सांठगांठ ऐसी है कि वे 50-50 प्रतिशत राशि हड़प रहे हैं। कर्मचारी काजू-बादाम सहित कॉस्मेटिक सामान तक घर ले जा रहे हैं। ऐसे कर्मचारी भी हैं जो परिवार के सदस्यों को बीमार बता कर दवा लिखवाई और घरेलू सामान खरीदा। *(रा.प., 11.09.22)*

भारत में घट गई कुपोषितों की संख्या

देश में 15 साल के दौरान कुपोषितों की संख्या में कमी आई है। वर्ष 2004-2006 में यह संख्या 24.78 करोड़ थी, जो 2019-2021 में घटकर 22.43 करोड़ रह गई। हालांकि, वयस्कों में मोटापा और महिलाओं में एनीमिया की समस्या बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में खाद्य व कृषि नीतियों का लक्ष्य स्वस्थ आहार, खाद्य सुरक्षा व पोषण परिणामों को बढ़ावा देना है।

निम्न-मध्यम आय वाले देशों में सबसे प्रमुख उदाहरण भारत है। जहां खाद्य और कृषि नीति ने सस्ती खाद्य कीमतों, सार्वजनिक खरीद व खाद्य भंडार को बढ़ावा दिया है। मध्य और निम्न आय वालों को अनाज, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पर्याप्त सब्सिडी दी जाती है। भारत में आंगनबाड़ी केंद्रों ने कुपोषण दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत बच्चों व गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार उपलब्ध कराया जाता है।

(रा.प., 08.07.22)

हाइड्रोजन ईंधन बस उतारी सड़क पर

भारत में प्रदूषण दूर करने के लिए नए-नए प्रयास हो रहे हैं। इसी क्रम में हाल ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल बस पुणे की सड़कों पर उतारी। इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और निजी कंपनी केपीआइटी ने मिलकर तैयार किया है। ईंधन सेल टेक्नोलॉजी बस को पावर देने के लिए हाइड्रोजन व हवा का इस्तेमाल कर बिजली पैदा करती है। बस में धुंआ नहीं सिर्फ पानी निकलता है।

जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाइड्रोजन विजन का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए अहम है। इसके जरिए आत्मनिर्भर भारत और सुलभ स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को भी पूरा किया जा सकेगा। यह ईंधन रिफाइनिंग, उर्वरक, इस्पात और सीमेंट उद्योग के लिए भी उपयोगी होगा।

(रा.प., 23.08.22)

इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर बनेगा भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत के विकास में विज्ञान उस ऊर्जा की तरह है, जिसमें हर क्षेत्र व हर राज्य के विकास को तेज गति देने की सामर्थ है। भारत अब चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने की ओर बढ़ रहा है। अमृतकाल में भारत अनुसंधान और इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर बनेगा। इसके लिए हमें एक साथ अनेक मोर्चों पर काम करना है।

गुजरात साइंस सिटी में आयोजित केंद्र-राज्य विज्ञान सम्मेलन को वर्चूअल संबोधित करते हुए उन्होंने यह विचार रखे। उन्होंने कहा विज्ञान और तकनीक से जुड़े शोध को अब स्थानीय स्तर तक लेकर जाने की जरूरत है। आने वाल 25 साल भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आने वाले भारत की नई पहचान और ताकत का निर्धारण करेगा।

(रा.प., 11.09.22)

महिलाओं को मिलेगी एनीमिया से मुक्ति

महिलाओं को अब 100 दिन आयरन टेबलेट लेने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ एक इंजेक्शन से एनीमिया (खून की कमी) से मुक्ति मिल जाएगी। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज ने अमेरिका की जैफरसन यूनिवर्सिटी व कर्नाटक के जेएन मेडिकल कॉलेज के साथ 'इंजेक्टेबल आयरन' पर देश का सबसे बड़ा ट्रायल शुरू किया है।

अस्पताल के सीनियर प्रोफेसर और प्रोजेक्ट इन्वेस्टीगेटर डॉ. सुधीर मेहता के मुताबिक जयपुर के सांगानेर, चाकसू, जमवारामगढ़ , बस्सी ब्लॉक के अलावा आमेर सहित अन्य सीएचसी को प्रोजेक्ट में शामिल किया गया हैं। 7240 गर्भवतियों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें से 813 ऐनिमियाग्रस्त पाई गई इनमें से 268 को ओरल रूटीन दवा जबकि 545 को इंजेक्टेबल श्रेणी में रखते हुए इंजेक्शन लगाए गए। जिसके परिणाम अच्छे रहे हैं। ट्रायल सफल रहा तो देश को एनीमिया मुक्त बनाने में यह मील का पत्थर साबित होगा।

(दै.भा., 10.07.22)

पहुंच रहा हैं ओजोन परत को नुकसान

सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा ओजोन परत ही करती है। एसी व फ्रिज में कूलिंग के लिए क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन गैस का उपयोग किया जाता है। इनमें से निकली क्लोरीन गैस निचले वायुमंडल को पार करते हुए ओजोन परत तक पहुंचती है, वहां उसके अणुओं को तोड़ती है।

भारत में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले शीर्ष पांच राज्यों में राजस्थान भी शामिल है। नेशनल फैमेली हेल्थ सर्वे-5 के अनुसार राजस्थान के 53.6 प्रतिशत घरों में एसी व फ्रिज इस्तेमाल हो रहे हैं।

राजस्थान से आगे 4 राज्यों में चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब व हरियाणा है। राजस्थान विश्वविद्यालय, पर्यावरण विज्ञान विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर प्रमा सोलोमन का कहना है कि इससे बचने के लिए जरूरी है, ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करना, जिनमें क्लोरीन के स्थान पर हाइड्रोजन का उपयोग हो।

(रा.प., 16.09.22)

शहरों में रात की तेज रोशनी जीवन में कर रही है 'अंधेरा'

देश दुनिया के बड़े शहरों में बढ़ रहा तेज रोशनी का चलन भले ही लोगों को लुभाता हो, लेकिन इससे पर्यावरण के साथ ही इंसान और जीव-जन्तु भी तबाह हो रहे हैं। आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट स्टेट ऑफ द साइंस 2022 के अध्ययन के अनुसार 2012 के बाद से प्रकाश प्रदूषण की तेजी और भू-क्षेत्र को कवर करने की गति 1.8 प्रतिशत से 2.2 प्रतिशत तक हर साल बढ़ रही है। शोध में कहा गया है कि दुनिया की 80 फीसदी आबादी प्रकाश प्रदूषित वातावरण में रह रही है। अमरीका-यूरोप के कई शहरों में तो प्रकाश प्रदूषण 99 प्रतिशत तक है।

अध्ययन में कहा गया है कि बढ़ते प्रकाश प्रदूषण की वजह से मानव और जीव जंतुओं में नींद का चक्र टूट रहा है। आंखें अंधेरे में कम देख पा रही है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। इससे कई बीमारियों में इजाफा हो रहा है। यह ही नहीं कृत्रिम प्रकाश से कई जीव-जंतु कम या गायब हो गए हैं और इसकी मार वनस्पति पर भी पड़ रही है।

(रा.प., 21.09.22)

द्रौपदी मुर्मू ने संभाला राष्ट्रपति पद

देश में पहली बार आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के गौरवपूर्ण पद पर निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने संसद भवन में राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और दोनों सदनों के सांसदों व देश के समस्त नागरिकों की आशा, अकांक्षा और अधिकारों के प्रति नए दायित्वों को निभाने के लिए आश्वस्त किया।

महामहिम का संदेश है 'हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आजाद हिंदुस्तान के नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी, उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में तेज गति से काम करना होगा। अमृत काल की सिद्धी का रास्ता दो पटरी पर आगे बढ़ेगा-सबका प्रयास और सबका कर्तव्य।' यह लोकतंत्र की ही शक्ति है एक गरीब घर की आदिवासी बेटी सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। सदियों से वंचित और विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि संथाल क्रांति, पाइका क्रांति से लेकर कोल क्रांति और भील क्रांति ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज के योगदान को सशक्त किया था। सामाजिक उत्थान एवं देश-प्रेम के लिए 'धरती आबा' भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान से हमें प्रेरणा मिली है। *(रा.प. एवं दै.भा., 22.07.22)*

भारत कृषि क्षेत्र में वैश्विक अगुआ बने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें टेक्नोलॉजी की मदद से कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाना होगा। इस तरह भारत आत्मनिर्भर बनने के साथ ही कृषि क्षेत्र में वैश्विक रूप से अगुआ बन सकता है।

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जीवनयापन में सुगमता लाने, सर्विस डिलीवरी को पारदर्शी बनाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो देश में तेजी से हो रहा शहरीकरण कमजोरी की बजाय एक ताकत बन सकता है। प्रधानमंत्री ने आयात को कम करने और निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्यों को ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। *(दै.भा., 08.08.22)*

'भारत' ब्रांड के तहत बिकेंगे उर्वरक

उर्वरकों की चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए केंद्र ने प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना के तहत एक देश एक फर्टिलाइजर योजना लागू की है। इससे आगामी रबी सीजन में किसानों को एक जैसी खाद मिलेगी। यह कंपनियों के बजाय भारत ब्रांड नाम से जानी जाएंगी। इस योजना के अंतर्गत यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके 'भारत' ब्रांड के नाम से उपलब्ध होंगे।

केंद्र ने यह निर्देश सभी उर्वरक कारखानों, ट्रेडिंग और मार्केटिंग कंपनियों को दिया है। खाद की बोरी पर एक साइड़ के दो तिहाई हिस्से पर नए ब्रांड और लोगों का उल्लेख होगा। बाकी एक तिहाई में कंपनी अपना ब्योरा और निर्धारित तथ्य प्रिंट करेगी। हर बोरी पर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना छपा रहेगा। खाद की बोरियों पर दर्ज प्रतीक चिन्ह (लोगो) से यह स्पष्ट हो जाएगा कि उर्वरक केंद्रीय सब्सिडी वाली है। *(रा.प., 26.08.22)*

लंपी वायरस का स्वदेशी टीका तैयार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकारें मवेशियों में ढेलेदार त्वचा रोग (लंपी स्किन डिजीज) के प्रसार को नियंत्रित करने की कोशिशों में जुटी हैं। इसकी रोकथाम के लिए एक स्वदेशी टीका विकसित किया गया है।

उन्होंने कहा हम 2025 तक पशुओं के 100 प्रतिशत टीकाकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। कई राज्य मवेशियों में फैले इस रोग से जूझ रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में लंपी वायरस नाम की इस बीमारी से पशुधन का नुकसान हुआ है। यह किसानों की आय को प्रभावित करता है। *(रा.प., 13.09.22)*

प्रदेश में जारी हुई नई हस्तशिल्प नीति

राजस्थान में पंजीकृत छह लाख हस्त-शिल्पियों के लिए करीब डेढ़ साल के इंतजार के बाद नई हस्तशिल्प नीति जारी कर दी गई है। केबिनेट से मंजूर प्रदेश की इस पहली नीति में हस्तशिल्पियों के लिए सामाजिक सुरक्षा के कई प्रावधान किए गए हैं। हस्तशिल्पियों को तीन लाख रुपए तक के ऋण पर देय ब्याज अब सरकार वहन करेगी।

राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हस्तशिल्पियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान भी नीति में शामिल है। इसके अलावा हस्तशिल्पियों को समूह बीमा मुहैया कराने, हर साल राज्यस्तरीय पुरस्कार देने, मेलों व प्रदर्शनियों में सहभागिता भत्ते में वृद्धि करने, हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहित करने, मार्केटिंग की व्यवस्था करने जैसे कई प्रावधान इस नीति में शामिल किए गए हैं। *(रा.प., 30.08.22)*

जैविक उत्पादों को मिला ग्लोबल बाजार

भारतीय जैविक उत्पादों को ग्लोबल बाजार मिलने लगे हैं। इससे देश का जैविक उत्पादों का निर्यात भी बढ़ रहा है। वर्ष 2019 से 2021 के बीच भारत ने अमरीका-यूरोप सहित कई देशों को 1.98 करोड़ टन जैविक उत्पादों का निर्यात किया, जिससे किसानों को 20 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक राशि प्राप्त हुई है।

निर्यात में 50 फीसदी से भी अधिक उत्पाद अमरीका और 37 फीसदी उत्पात यूरोपियन यूनियन के देशों को निर्यात किया गया। विदेशों में भारतीय जैविक उत्पादों की मांग बढ़ी है। *(रा.प., 11.08.22)*

छोटे कारोबारियों के लिए 'रैम्प' योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'उद्यमी भारत' प्रोग्राम के दौरान 6000 करोड़ रुपए की 'रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉरमेंस (रैम्प) योजना की शुरूआत की है। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) की योजनाओं के प्रभाव में वृद्धि के साथ राज्यों में एमएसएमई की कार्यान्वियन क्षमता और कवरेज को बढ़ाना है।

यह योजना इनोवेशन को बढ़ावा देने, गुणवत्तापूर्ण मानकों को विकसित कर नए व्यवसाय और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने व उद्योग 4.0 के जरिए आत्मनिर्भर भारत अभियान को समर्थन प्रदान करेगी। एमएसएमई क्षेत्र ने पिछले आठ साल में आत्मनिर्भर भारत को एक आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई है। यह योजना 6.3 करोड़ उद्यमों को लाभान्वित करेगी। इसमें विश्व बैंक भी सहायता दे रहा है। *(रा.प., 01.07.22)*

भ्रष्टाचार में राजस्थान का दूसरा स्थान

देश में वर्ष 2021 के जारी भ्रष्टाचार की कार्रवाई के आंकड़ों में राजस्थान का दूसरा नंबर है। प्रदेश में एसीबी की भ्रष्ट अधिकारियों व कार्मिकों के खिलाफ लगातार एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। लेकिन सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा। जनवरी से अगस्त 2021 की तुलना में इस वर्ष 8 माह में करीब 27 फीसदी भ्रष्टाचार के मामले बढ़ गए। इस अवधि में गत वर्ष 293 तो इस वर्ष 399 प्रकरण दर्ज हुए हैं।

राजस्थान में हर साल भ्रष्ट अधिकारी व कार्मिकों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई बढ़ती जा रही है। ब्यूरो को लोगों की जागरूकता से भी सहायता मिल रही है। राजस्थान में पंचायती राज विभाग रिश्वतखोरों को बचाने में अग्रणी है। अभियोजन स्वीकृति अटकाने के मामले में पंचायती राज विभाग का पहला नंबर है। विभाग में एसीबी के 107 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति के लिए लंबित है। *(रा.प., 15.09.22)*

ईडी के अधिकार मनमानी नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन कर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को दिए गए अधिकारों को सही ठहराया है। जस्टिस ए.एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी रवि कुमार की पीठ ने 2018 में किए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली 243 याचिकाओं पर फैसला सुनाया। पीठ ने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच, छापेमारी, बयान दर्ज करने, गिरफ्तार करने और समन जारी करने के अधिकारों को सही बताया।

फैसले में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की गिरफ्तारी की शक्ति मनमानी नहीं है। दुनियाभर में आम अनुभव है कि मनी लॉन्ड्रिंग वित्तीय प्रणाली के अच्छे कामकाज के लिए खतरा हो सकता है। यह कोई साधारण अपराध नहीं है। पीठ ने कहा कि विभिन्न आपराधिक कृत्यों से पैदा किए गए धन को वैश्विक स्तर पर छिपाने की क्रिया भारत की संप्रभुता और अखंडता पर हमला है।

(दै.भा., 28.07.22 एवं 29.07.22)

एसीबी भ्रष्ट 'मछलियों' को पकड़ने का कांटा

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के महानिदेशक बी.एल. सोनी ने व्यापारियों से कहा है कि आपकी कमाई को कोई सरकारी अधिकारी लूट ले जाए, यह बर्दास्त नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी अधिकारी हो, रिश्वत मांग रहा है तो टोल फ्री नंबर 1064 पर सूचना दें। सूचना पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। अब एसीबी ट्रेप के साथ और ट्रेप के बाद भी आपके साथ है। ट्रेप के बाद भी अगर आपका काम कोई दूसरा अफसर अटका रहा हौ तो एसीबी अधिकारी आपके साथ संबंधित आफिस जाएगा।

एमआई रोड स्थित चैंबर भवन में एसीबी अधिकारियों और व्यापारियों के बीच ओपन हाउस मीटिंग में सोनी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि एसीबी भ्रष्ट मछलियों को पकड़ने का कांटा है, आप दाना फेंकिए, हम ऐसे भ्रष्ट अफसर को पकड़ लेंगे, जो आपसे रिश्वत मांग रहा है। राजस्थान चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सचिव डॉ. केएल जैन ने कहा कि भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने में हम भी काफी जिम्मेदार हैं। अपना काम कराने के लिए गलत रास्ता अपनाते हैं। बस यही भ्रष्टाचार है। हमें भ्रष्टाचार का विरोध मिल कर करना होगा। *(दै.भा. एवं रा.प., 18.09.22)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
डूंगरपुर	मितार्थ श्रीमाली विकास गुप्ता	प्रबंधक, सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., प्रधानशाखा शाखा प्रबंधक, सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लि.,कनबा	1,25,000 25,000	*दै.भा. एवं रा.प., 09.07.22*
टौंक	भरतलाल सैनी दिनेश सैनी	चैयरमैन, नगर पालिका, टोडारायसिंह पी.ए, संविदा कर्मचारी, नगर पालिका, टोडारायसिंह	1,50,000	*रा.प. एवं दै.भा., 19.07.22*
हनुमानगढ़	सुभाष स्वामी जगरूप सिंह	कनिष्ट लिपिक, कलेक्टरेट हनुमानगढ़ बिचौलिया	2,00,000	*दै.भा., 27.07.22*
अलवर	सुरेश कुमार जाट	हेड कांस्टेबल, बानसूर थाना, अलवर	1,40,000	*रा.प., 03.08.22*
जयपुर	हरिनारायण शर्मा	एसएसओ, गोविन्दगढ़ थाना, जयपुर ग्रामीण क्षेत्र	10,00,000	*दै.भा. एवं रा.प., 26.08.22*
अलवर	अरुण शर्मा रमेश चंद सैनी	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, थानागाजी दलाल	2,00,000	*दै.भा. एवं रा.प., 07.09.22*
सिरोही	अशोक सिंह चारण अनिल कुमार अभिमन्यु सिंह	थानाधिकारी, मण्डार, सिरोही दलाल दलाल	4,00,000	*रा.प., 22.09.22*

बिजली मीटर सही, गणना हो रही गलत

जयपुर डिस्कॉम में उपभोक्ता के मीटर में सही रीडिंग होने के बावजूद गलत रीडिंग गणना के बिल दिए जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी में पिछला और वर्तमान पठन की गणना ही गलत हो रही है। रीडिंग की औसत गणना की गणित भी गलत है। बिल जमा करवाने के बावजूद दुबारा पांच गुना राशि के बिल भेजे जा रहे हैं। इससे उपभोक्ता गलत बिल में संशोधन के लिए 'चक्करघिन्नी' हो रहे हैं।

उपभोक्ता को हाईटेक व आईटी सिस्टम से बिल देने के नाम पर प्राइवेट एजेंसी बीसीआईटीएस को पिछले कई सालों से बड़ी राशि का भुगतान किया जा रहा है। लेकिन सिस्टम में सुधार नहीं होने से उपभोक्ता ही नहीं विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी परेशान हो रहे हैं। बिल सही कराने के लिए काम का बोझ ज्यादा होने से अधिकारी सही रूप से मॉनिटरिंग भी नहीं कर पा रहे हैं।

(दै.भा., 09.09.22)

रूफटॉप सोलर पर अटकाई सब्सिडी

सौर ऊर्जा के लिए लोग रूफटॉप सोलर लगाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रदेश की बिजली कंपनियां इसमें रुकावट बनी हुई है। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रूफटॉप पैनल पर सब्सिडी देने के आदेश छह महीने पहले जारी कर दिए। बावजूद इसके बिजली कंपनियां अब तक लोगों को इसका लाभ नहीं दे पाई।

यह सब्सिडी 30 से 40 प्रतिशत तक है, जो लम्बे समय से बंद है। डिस्कॉम प्रबंधन एक बार फिर निविदा प्रक्रिया पूरी करने का रटारटाया तर्क दे रही है। जबकि प्रदेश में 55 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर पैनल (सब्सिडी के साथ) लगाए जाने हैं। जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम की तरफ से इसका जिम्मा अजमेर डिस्कॉम के पास है। *(रा.प., 07.07.22)*

दूर हो रहा अपना घर ग्रीन करने का सपना

भारत समेत दुनियाभर में परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बावजूद लोगों को अपना घर ग्रीन करना आसान नहीं हो पाया है। लालफीताशाही की वजह घरों पर लगाए जाने वाले सोलर प्लांट को ग्रिड से जुड़वाने की औपचारिकता में लोगों के पसीने छूट रहे हैं।

सोलर प्लांट पर जीएसटी बढ़ाने व कस्टम ड्यूटी लगाने से यह और भी महंगा हो गया है। सस्ती व साफ बिजली के लिए सौर ऊर्जा पर जोर होने के बावजूद बड़े शहरों में भी लोगों के यहां सोलर प्लांट कम लग सके हैं। इसके लिए जागरूकता के अभाव के साथ ही सरकारी महकमों की ढिलाई भी कम जिम्मेदार नहीं है। सोलर प्लांट की नेट मीटरिंग मुश्किल है। ऐसे में लोग डिस्कॉम कार्यालयों के चक्कर खाते रहते हैं। *(रा.प., 20.08.22)*

सोलर पैनल पर मिलेगी सब्सिडी

मकान की छत पर सोलर पैनल लगाकर (सब्सिडी युक्त) सस्ती बिजली उत्पादन करने की हजारों लोगों की उम्मीद जल्द ही पूरी होगी। बतौर नोडल एजेंसी अजमेर डिस्कॉम ने प्रोजेक्ट के टेंडर फाइनल कर दिए हैं।

जल्द ही बिजली उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी मिल सकेगी। अभी उपभोक्ता पिछले एक साल से सब्सिडी मिलने का इंतजार कर रहे थे। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान को 55 मेगावाट के रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट का आवंटन किया है, जिसमें सब्सिडी दी जाएगी। *(रा.प., 25.09.22)*

सौर ऊर्जाः कम हो रहा कार्बन उत्सर्जन

सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले पायदान पर खड़ा राजस्थान रूफटॉप सोलर प्लांट में तीसरे नंबर पर है। अभी 30 हजार इमारतों की छत पर लगे 777 मेगावॉट के सोलर प्लांट से प्रति वर्ष करीब 23 करोड़ किलो कार्बन उत्सर्जन कम हो रहा है, जो 10 लाख पेड़ लगाने के समान है।

शहरी क्षेत्र में करीब 40 लाख आवासों में 10 प्रतिशत को भी लक्ष्य बनाएं तो राजस्थान में सस्ती बिजली और पर्यावरण संरक्षण को लेकर तस्वीर बदल सकती है। लेकिन सरकार ने मार्च, 2025 तक रूफटॉप सोलर प्लांट का केवल एक हजार मेगावाट तय किया है, जबकि विशेषज्ञों ने इसे बढ़ाकर घर-घर की छत पर सोलर प्लांट की जरूरत बताई है। गौरतलब है कि परंपरागत संयंत्र से बिजली उत्पादन न केवल महंगा है बल्कि इससे प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है।

(रा.प., 20.08.22)

प्रदेश होगा अणु ऊर्जा से संपन्न

अगले दो वर्ष में अणु ऊर्जा से संपन्न राजस्थान विद्युत उत्पादक राज्यों की अग्रणी पंक्ति में होगा। सीकर जिले के खंडेला इलाके के रोयल गांव में प्रस्तावित यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के प्रोजेक्ट को यूरेनियम उत्खनन के लिए एलओआइ जारी करने के साथ ही खनन की तैयारी तेज हो गई है।

रोयल गांव में 120 लाख टन यूरेनियम का भंडार है। सुरंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। पर्यावरण एनओसी, बिजली कनेक्शन व राजस्व विभाग से भूमि की एनओसी मिलने के बाद दो साल में यूरेनियम की खुदाई शुरू होने की उम्मीद है। उत्खनन के बाद प्रदेश में नए विद्युत उत्पादन प्लांट शुरू हो सकेंगे। इससे राज्य को 40 साल तक 800 मेगावॉट बिजली प्राप्त हो सकेगी। इस प्रोजेक्ट से राजस्थान में छह हजार करोड़ से अधिक के निवेश की संभावना है, जिससे रोजगार की नई राहें भी खुलेंगी।

(रा.प., 13.07.22)

पहाड़ी पर पानी से बनाएंगे बिजली

कोटा के समीप जवाहर सागर बांध से सटी पहाड़ी को बिजली उत्पादन के लिए चिन्हित किया गया है। पहाड़ी पर पानी का स्टोरेज होगा। यहां स्टोरेज टैंक बनेगा। पहले बांध से यहां पानी एकत्रित किया जाएगा और जरूरत के आधार पर नीचे लाकर टरबाइन के जरिए बिजली उत्पादन किया जाएगा। यहां 200 मेगावाट क्षमता का पम्प स्टोरेज प्लांट बनाने की तैयारी चल रही है। इससे एक दिन में अधिकतम 16 लाख यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी।

राजस्थान में ऐसा पहला प्रोजेक्ट होगा। सरकार इसकी कमान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को दे रही है। प्रोजेक्ट के निर्माण की समय सीमा अधिकतम तीन साल होगी। जवाहर सागर बांध पर अभी पनबिजलीघर (हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन) संचालित है। यहां 33 मेगावाट की तीन यूनिट है। सालभर में करीब 8 महीने बिजली उत्पादन होता है। *(रा.प., 19.07.22)*

धरातल पर उतरेंगी पेयजल परियोजनाएं

जयपुर शहर के लाखों लोगों की पेयजल जरूरतों को पूरी करने के लिहाज से दिसंबर का महीना महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्योंकि दिसंबर के पहले सप्ताह में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत वाली चार परियोजनाएं धरातल पर उतरेंगी। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद शहर की 10 लाख से ज्यादा की आबादी लाभान्वित होगी।

इन परियोजनाओं में बीसलपुर ट्रांसफर मेन परियोजना पर 69.58 करोड़ रुपए, लक्ष्मण डूंगरी पेयजल परियोजना पर 16.83 करोड़ रुपए, भट्टा बस्ती पेयजल परियोजना पर 5.79 करोड़ रुपए तथा उद्योग नगर पेयजल परियोजना पर 5.96 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी परियोजनाओं को एक वर्ष की अवधि में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 563 करोड़ रुपए की लागत वाला बीसलपुर-पृथ्वीराज नगर प्रोजेक्ट भी अक्टूबर माह में पूरा होने वाला था।

(रा.प., 27.09.22)

पेयजल लाइन व खराब मीटर बदलेंगे

केंद्र सरकार के अमृत-2 के तहत 1266 करोड़ रुपए के बजट से जल्द ही कई समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है। इस बजट से जयपुर शहर की लड़खड़ाती पेयजल व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा। इससे पूरे शहर की जर्जर पेयजल लाइनों और करीब 150 लाख खराब मीटरों को बदला जा सकेगा। पंप हाउस पर पुराने सभी पंप बदलना और पंप हाउसों पर सोलर से विद्युत आपूर्ति जैसे काम होंगे।

इससे राजस्व छीजन कम हो सकेगी साथ ही 24 घंटे पेयजल सप्लाई की व्यवस्था को मूर्तरूप दिया जा सकेगा। लम्बे समय से बजट के अभाव के चलते जर्जर पेयजल लाइनों के कारण दूषित पानी आने की शिकायतें आती रहती थी तो मीटर खराब होने से राजस्व को नुकसान होता था। अब इससे राहत मिलने की उम्मीद बंधी है।

(रा.प., 12.08.22)

पेयजल कनेक्शन पर क्यों नहीं है मीटर?

जयपुर शहर में 2 लाख से ज्यादा पेयजल कनेक्शनों पर तीन साल में भी मीटर नहीं लग पाए हैं। ऐसे में इन उपभोक्ताओं को औसत उपभोग के पानी का बिल दिया जा रहा है। इस कारण तीन साल बाद भी उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री की ओर से 15 हजार लीटर का जल शुल्क योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है।

उपभोक्ताओं ने पानी के मीटर लगाने और औसत उपभोग का दायरा 20 हजार 800 लीटर से घटा कर 15 हजार लीटर करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने 08 मार्च 2019 को महीने में 15 हजार लीटर पानी का उपभोग करने वाले परिवारों का पेयजल शुल्क माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन विभाग के इंजीनियरों ने नियम ही अव्यवहारिक बना दिए हैं और योजना को केवल मीटर्ड कनेक्शनों पर ही मान्य किया है।

(दै.भा., 06.09.22)

जल जीवन मिशन की कछुआ चाल

जलदाय विभाग की लापरवाही से प्रदेश में जल जीवन मिशन पिछड़ रहा है। मिशन के तहत ग्रामीण घरों तक जल कनेक्शन जारी करने में प्रदेश देश में 29 वें नंबर पर है। केंद्र सरकार की ओर से आवंटित बजट भी खर्च नहीं हो पा रहा है। जल कनेक्शन के लिए बड़ी पेयजल योजनाएं तैयार की गई है।

विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में 32 लाख कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही अफसरों और इंजीनियरों ने 60 दिन में ही ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख 6 हजार से ज्यादा कनेक्शन जारी कर दिए हैं। अभी तक 26 लाख 30 हजार कनेक्शन जारी हो चुके हैं।

(रा.प., 04.07.22)

टाउनशिप में रहने वालों को राहत

जयपुर शहर में सवा चार लाख मल्टीस्टोरी बिल्डिंग के फ्लैट व रेजिडेंशियल टाउनशिप में पानी के कनेक्शन का चार्ज जल्द ही कम होगा। फ्लैट में कनेक्शन का चार्जेज 42 रुपए प्रति वर्ग फीट के बजाय अब 25 से 30 रुपए प्रति वर्ग फीट लगेगा। इसके साथ ही केवल 5 हजार वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की अनिवार्यता रहेगी।

जलदाय विभाग के चीफ इंजीनियर (शहरी) की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने बिल्डर्स, टाउनशिप डवलपर्स एवं रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन व क्रेडाई के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर नई पॉलिसी पर चर्चा की।

(दै.भा., 09.07.22)

रोज लाखों लीटर भू-जल दोहन?

बीसलपुर बांध में रोजाना 5 सेमी यानी 25,000 लाख लीटर पानी आ रहा है। इसमें से जयपुर, अजमेर व टोंक को 9500 लाख लीटर पानी की सप्लाई हो रही है। इसके बावजूद जलदाय विभाग बीसलपुर प्रोजेक्ट के सिस्टम से जुड़े 1400 ट्यूबवेल से हर दिन पानी का दोहन किया जा रहा है। इन ट्यूबवेल को बंद करने या रोटेशन में चलाया जाए तो पानी की बचत हो सकती है।

कर्मचारियों का कहना है कि बीसलपुर में पर्याप्त पानी है। ऐसे में ट्यूबवेल को बंद कर देना चाहिए। इससे बिजली खर्च बचेगा। हर साल बारिश आते ही ट्यूबवेल को बंद कर रोटेशन से चलाते हैं, लेकिन इस बार इसको लेकर फैसला नहीं लिया गया है। चीफ इंजीनियर मनीष बेनीवाल का कहना है कि बीसलपुर में पर्याप्त पानी आने पर ट्यूबवेल को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

(दै.भा., 13.08.22)

बीसलपुर से व्यर्थ बह गया पानी

प्रदेश में इस बार 3 साल में सबसे अच्छा मानसून आया। राज्य की पॉलिसी है कि पानी की बूंद-बूंद व्यर्थ न जाए। पर प्रदेश की नदियों में बारिश का 23000 मिलीयन क्यूबिक मीटर पानी व्यर्थ बह गया। बनास नदी में लगातार पानी आने से बीसलपुर बांध एक महीने से ओवरफ्लो होता रहा। बांध के गेट खोलकर लगातार पानी छोड़ा जाता रहा और यह पानी व्यर्थ जाता रहा।

बनास नदी पर यदि अब तक ईसरदा बांध बन चुका होता तो यह पानी चंबल नदी में व्यर्थ नहीं जाता। ईसरदा बांध का 44 महीने में केवल 43 फीसदी ही काम हो पाया। ईसरदा बांध का निर्माण प्रोजेक्ट का वर्कआर्डर 615.17 करोड़ रुपए में मैसर्स ओममेटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड व डब्ल्यूआईपीएल की जॉइंट वेंचर कंपनी को 21 दिसंबर 2018 में दिया था, जो दिसंबर 2021 तक पूरा होना था।

(दै.भा., 29.09.22)

पेड़ों को काटे बगैर बन सकते हैं समृद्ध

कर्नाटक के होन्नाली के घने जंगल में करीब

80 साल की बुजुर्ग महिला पद्मश्री तुलसी गौड़ा बिना पढ़ाई-लिखाई के पेड़ों के बारे में दुर्लभ जानकारियां रखती है। जब वह किसी को पेड़ों और बीजों के बारे में बताती है तो लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। तुलसी ने अपनी पूरी जिंदगी कर्नाटक में बंजर जमीन को जंगलों में बदलने में समर्पित कर दी।

तुलसी कहती है पेडों को काटे बगैर इंसान समृद्ध बन सकते हैं। जब वह पेड़ों का महत्व बताती है तो गांव के लोग आदर से सिर झुका लेते हैं। पद्मश्री सम्मान लेने के लिए वह पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में बिना पैरों में कुछ पहने पहुंची थी। पूरी जिन्दगी में कभी जूते नहीं पहने। छात्रों से भरी बसें उनके घर पेड़ों के बारे में जानकारी लेने पहुंचती है, तो उनकी बांछे खिल उठती है। *(दै.भा.,05.09.22)*

पीएम श्री योजनाः बनेंगे मॉडल स्कूल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के मौके पर देशभर में 14 हजार 500 स्कूलों को विकसित व क्रमोन्नत करके पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) स्कूल में तब्दील करने की घोषणा की है। यह मॉडल स्कूल देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होंगे। देश के हर ब्लॉक में कम से कम एक पीएम श्री स्कूल होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इन स्कूलों में प्री-प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई आधुनिक, परिवर्तनकारी एवं समग्र अनुसंधान आधारित तरीके से होगी। यह स्कूल केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन होंगे। स्कूलों को विकसित करने का पूरा खर्च केंद्र उठाएगा। राज्य सरकारों से सरकारी स्कूलों को इनमें तब्दील करने के लिए प्रस्ताव मांगे जाएंगे। *(रा.प. एवं दै.भा., 06.09.22)*

मुख्यमंत्री ने महिलाओं को दिया तोहफा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में महिला निधि की स्थापना राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् के माध्यम से करने की घोषणा की थी। उन्होंने घोषणा के अनुसार महिला समानता दिवस पर महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक तरक्की के लिए महिला निधि योजना का लोकार्पण किया।

इस योजना के तहत 40 हजार रुपए तक के ऋण 48 घंटे में व 40 हजार रुपए से अधिक के ऋण 15 दिवस में आवेदित सदस्यों के समूह के बैंक खाते में जमा हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने 6 जिलों के 386 स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को 1.42 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान महिला निधि से ऋण के रूप में स्वीकृत की। *(दै.भा., 22.08.22)*

गांवों में बनाए जाएंगे खेल स्टेडियम

प्रदेश के 33 जिलों में 11 हजार 307 ग्राम पंचायत स्तर पर और करीब 352 ब्लॉक में खेल स्टेडियम तैयार होंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं निखरेंगी। खेल मैदान भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की राजीव गांधी खेल अभियान योजना के तहत आने वाले खेलों के लिए बनाया जाएगा।

खेल मैदान में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केट बॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, वालीबॉल, कबड्डी और क्रिकेट आदि खेलों को शामिल किया गया है। मैदान की तैयारी की मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर करेंगे। मैदान निर्माण पूरा होने के बाद उसके रख-रखाव एवं उपयोग की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत समिति की होगी। *(दै.भा., 11.07.22)*

प्रसव के दौरान जननी पर खतरा कायम

मां और शिशु की जान बचाने से जुड़ी जागरूकता मुहिम के बावजूद भारत में बीते 23 साल में 13 लाख गर्भवती महिलाओं की मौत हुई है। गर्भधारण के दौरान जटिलताओं और शिशु की डिलीवरी से मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 2022 में मातृ मृत्युदर का राष्ट्रीय औसत 103 है। दुनिया में प्रसव के दौरान होने वाली मौतों में भारत की हिस्सेदारी 12 फीसदी है।

भारत में मातृ मृत्युदर सालाना आधार पर 4.5 फीसदी घट रही है। संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य पाने के लिए इसमें वार्षिक आधार पर 5.5 फीसदी की गिरावट आनी चाहिए। सुधार के बावजूद मातृ मृत्युदर में राजस्थान पिछड़ा है। अच्छी खबर यह है कि धीरे-धीरे ही सही, गर्भवती महिलाओं की जान पर खतरा कम हो रहा है। *(रा.प., 21.07.22)*

78 फीसदी महिलाएं बैंक से जुड़ी

विश्व बैंक ने 2021 का ग्लोबल फिनडेक्स डेटाबेस जारी किया है। जारी डेटाबेस के अनुसार 123 देशों के सर्वे में सामने आया है कि पिछले 10 साल में दुनिया की तुलना में भारत में बैंक खातों की रफ्तार दोगुनी रही है। वर्ष 2011से 2021 के बीच दुनिया में बैंक खाते 23 प्रतिशत बढ़े, जबकि हमारे यहां 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 में दुनिया में 46.7 करोड़ बैंक खाते खुले जिनमें से 28.1 करोड़ बैंक खाते अकेले भारत के हैं।

भारत में बैंक खाते खुलने की रफ्तार सबसे तेज रही है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत की 78 फीसदी महिलाएं और 78 फीसदी गरीब आबादी भी बैंकों से जुड़ी है। महिलाओं और गरीबों के पास बैंक खाते होने से उनके खातों में सरकार द्वारा सीधा पैसा भेजने से घर में उनका फाइनेंशियल कंट्रोल और महत्व भी बढ़ा है। सर्वे के अनुसार देश में 23 करोड़ लोगों के पास अभी भी बैंक खाता नहीं है। उनमें से 43 प्रतिशत लोग बैंक दूर होने की वजह से खाता नहीं खुलवा रहे। *(दै.भा., 20.08.22)*

मुख्यमंत्री कन्यादान में बढ़ा बजट

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 24 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। इस निर्णय से योजना में प्राप्त होने वाले आवेदनों का शीघ्र निस्तारण संभव हो सकेगा तथा लाभार्थियों को सहायता राशि जल्द स्वीकृत की जा सकेगी।

योजना के तहत बजट में 48 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया था, जिसमें से अब तक 47.74 करोड़ रुपए का भुगतान कर आवेदकों को आर्थिक संबल दिया जा चुका है। अतिरिक्त 24 करोड़ रुपए से प्राप्त आवेदनों के साथ-साथ भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रकरणों का निस्तारण भी किया जा सकेगा। यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत बालिकाओं के विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए संचालित की जा रही है। *(रा.प., 02.09.22)*

कार में पिछली सीट पर सीट बेल्ट जरूरी

दुपहिया वाहन पर डबल सवारी के लिए जैसे हेलमेट लगाना जरूरी है, उसी तरह से कार की पीछे की सीट पर बैठने वाली तीनों सवारियों को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो अब यातायात पुलिस 1000 रुपए का चालान काटेगी। सड़क व परिवहन मंत्रालय के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने गाइडलाइन आने के बाद आदेश प्रभावी रूप से लागू कर दिए हैं।

शहर में अब तक कार की आगे की सीट पर सीट बैल्ट नहीं लगाने पर चालान की कार्रवाई की जाती थी। इस आदेश के लागू होने के बाद से कार की पीछे की सीट पर अब अधिकतम तीन व्यक्ति ही बैठ पाएंगे। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति बेल्ट नहीं लगाता तो चालान काट दिया जाएगा।

(रा.प. एवं दै.भा, 28.09.22)

ट्रैफिक सिस्टम होगा अपग्रेड

जयपुर शहर का ट्रैफिक सिस्टम जल्द ही अपग्रेड किया जाएगा। चौराहों व तिराहों पर लगे 234 सिग्नल्स का टाइमिंग रिसेट होगा। 50 नए ट्रैफिक पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। पहले फेज में 34 चौराहे/तिराहे और 16 चौराहे दूसरे फेज में सुधारे जाएंगे। ट्रैफिक सिग्नल के अलावा रोड स्ट्रिप, ब्लिंकर्स, राइट तथा लेफ्ट टर्निंग लेन और जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाएगी। साथ ही, 74 ब्लैक स्पॉट को भी सही किया जाएगा।

यह सभी काम ट्रैफिक पुलिस व जेडिए द्वारा किए जाएंगे। इस पर 3.80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ट्रैफिक लाइट्स, कैमरे व कंट्रोल रूम के मेंटेनेंस के लिए जेडीए ने दो करोड़ रुपए के वर्क आर्डर भी जारी किए हैं। बाकी काम एआरसी यानी एनुवल रेट कांट्रेक्ट पर होगा। गौरतलब है कि ब्लैक स्पॉट और खराब चौराहों पर दो साल में 401 दुर्घटनाओं में 199 लोगों की मौत हुई है। ट्रैफिक रिकार्ड के मुताबिक दिन में 238 और रात में 163 दुर्घटनाएं हुई है। *(दै.भा., 11.07.22)*

बदले जाएंगे सड़कों पर लगे संकेतक

देश में बढ़ते सड़क हादसों में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करके जुर्माना राशि में बढ़ोतरी की है। नियमों में भी सख्ती की गई है। अब केंद्र सरकार की सड़क मानकों का सृजन करने वाली देश की शीर्ष संस्था इंडियन रोड्स कांग्रेस (आईआरसी) ने कुछ सड़क चिन्हों में बदलाव किया है।

कई नए चिन्ह भी प्रकाशित किए गए हैं। आइआरसी के इन मानकों का समस्त सड़क निर्माण एवं विभागों एवं एजेंसियों को अब सख्ती से पालना करनी होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन और ट्रेफिक सिग्नल पर फ्री लेफ्ट टर्न के नए चिन्ह जारी किए गए हैं। पर्यटक स्थल जैसे कई अन्य चिन्ह भी नए अथवा बदले गए हैं। संस्करण में नई चिन्ह श्रेणियां, नए सड़क चिन्ह, नवीन परिभाषाएं तथा कुछ पुराने चिन्हों के स्वरूप में संशोधन किया गया है। राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ में कार्यरत सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ अश्विनी बग्गा ने भी आईआरसी को सुझाव भेजे थे, जिन्हें भी शामिल किया गया है। *(दै.भा., 14.09.22)*

रोडवेज बसों में लगे है प्रेशर हॉर्न?

वाहनों में हूटर या प्रेशर हार्न लगाना गलत है, फिर भी जेसीटीएसएल व रोडवेज की बसों में इनका खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। जेसीटीएसएल की लो-फ्लोर बसों में तो प्रेशर हॉर्न ही लगे हुए हैं। भीड़ भरी सड़कों पर बसों के ड्राइवर प्रेशर हॉर्न बजा रहे हैं। ये हॉर्न ध्वनि प्रदूषण तो फैला ही रहे हैं, साथ ही इनसे दुपहिया वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को परेशानी हो रही है। इन पर न तो जेसीटीएसएल व रोडवेज प्रशासन ध्यान दे रहा है और न ही आरटीओ, न ही ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही है।

केंद्रीय मोटर यान नियम में स्पष्ट है कि कोई भी वाहन ऐसा बहुस्तर हॉर्न नहीं लगाएगा, जिससे विभिन्न प्रकार की ध्वनि निकलती हो या कर्कश, कंपित, तेज या ज्यादा शोर उत्पन्न होने वाली कोई दूसरी युक्ति लगी हो। केवल एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, आरटीओ वाहनों पर ही लगाए जा सकते हैं। अन्य कोई भी प्रेशर हॉर्न या हूटर लगाता है तो 500 से लेकर 4000 रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। *(रा.प., 26.07.22)*

सीट बेल्ट नहीं लगाने से रोज 41 मौतें

शुरूआती जांच में पता चला कि टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त की सड़क हादसे में सीट बेल्ट नहीं लगाने से मौत हुई थी। कानून के मुताबिक कार में आगे ही नहीं पीछे की सीट पर बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। सेव लाइफ फाउंडेशन के 6 बड़े शहरों में किए गए सर्वे के मुताबिक सिर्फ 2 फीसदी लोग ही पीछे की सीट बेल्ट लगाते हैं।

सर्वे में सामने आया है कि 62 फीसदी लोगों को यह पता नहीं है कि रियर सीट बेल्ट जरूरी है। देश में साल 2020 में सड़क हादसों में 15,146 लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से जान गंवाई। यानी 41 मौतें रोजाना। सीट बेल्ट लगाना आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा का कवच है। कंपनियां रियर सीट का अलार्म दें यह भी जरूरी है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है इसकी आदत। *(दै.भा., 06.09.22)*

जानलेवा सड़कें, बढ़ गए भीषण हादसे

केंद्र सरकार देशभर में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार कर रही है। इसके लिए सरकार प्रतिदिन 50 किलोमीटर के हिसाब से वित्त वर्ष 2022-23 में 18,000 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य लेकर चल रही है। विड़ंबना यह है कि ये राजमार्ग लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार वर्ष 2020 में 1 लाख 31 हजार 714 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। जबकि वर्ष 2019 में मृतकों की संख्या 1 लाख 51 हजार 113 रही।

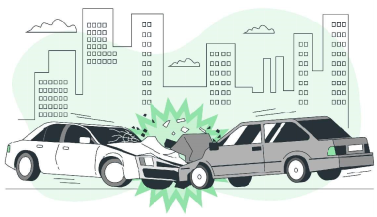

भले ही सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या कम दिख रही हो, लेकिन प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो प्रति सौ हादसों में वर्ष 2020 में 36 लोगों की मौत हुई। जबकि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में प्रति सौ हादसों पर 33.7 लोगों की मौत हुई। अर्थात्, सड़क हादसों में लोगों की जान जाने का एक बड़ा कारण हादसों की भीषणता और घायलों को समय पर इलाज नहीं मिल पाना है।

(रा.प., 04.07.22)

उपभोक्ता फैसले

छात्रा की मौत पर कॉलेज को देना होगा 25 लाख का जुर्माना

बेंगलुरू में मंडूडा एजुकेशन ट्रस्ट के वोग इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में स्वर्णा जसवंत ने 2010 में बीएसई एफएडी कोर्स में दाखिला लिया था। सेकेंड ईयर में इंस्टीट्यूट बेंगलुरू रूलर स्थित नई निर्माणाधीन बिल्डिंग में स्थानांतरित कर दिया गया। वहां छात्रा स्वर्णा जसवंत की निर्माणाधीन बिल्डिंग से नीचे गिरने पर मौत हो गई। मामला राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में दाखिल हुआ।

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने कॉलेज प्रशासन की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए उन्हें आदेश दिया कि वह मृतक छात्रा के परिजनों को 25 लाख रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर 9 फीसदी ब्याज सहित दे। आयोग ने कॉलेज प्रशासन की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि कॉलेज प्रशासन ने निर्माणाधीन बिल्डिंग में दूसरी मंजिल पर छात्र-छात्राओं को जाने से रोकने के लिए कोई प्रबंध नहीं किए थे। न तो वहां पर कोई दरवाजा लगाया गया था और न ही कोई रूकावट अथवा गार्ड को तैनात किया गया था। कॉलेज प्रशासन की लापरवाही से यह हादसा हुआ है और इसके लिए वह पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के लिए बाध्य है। *(दै.भा., 25.07.22)*

सांप काटने से आया था अटैक; बीमा कंपनी क्लेम दें

दौसा जिले के नांगल राजावतान निवासी मुकेश मीना ने राज्य उपभोक्ता आयोग में बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग दौसा के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दर्ज कराई। मीना ने राज्य आयोग को बताया कि पिता लल्लूराम ने 17 जून 2014 को 10 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कराया था। सांप के काटने से उनके पिता को मौत हो गई। उन्होंने क्लेम का दावा किया, लेकिन कंपनी ने डेथ अटैक से कहकर क्लेम खारिज कर दिया। जिला आयोग ने भी बीमा कंपनी को सही माना, जबकि उनकी मृत्यु सांप काटने से हुए अटैक के कारण हुई थी।

मामले की सुनवाई पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने सांप के काटने से आए अटैक के चलते हुई बीमित व्यक्ति की मौत को नेचुरल मृत्यु की बजाय एक्सीडेंटल मृत्यु माना। आयोग ने कहा बीमित व्यक्ति लल्लूराम को सांप के काटने से अटैक आया था। आयोग ने बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह परिजनों को 10 लाख रुपए नौ फीसदी ब्याज सहित दे। इसके अलावा 20 हजार रुपए मानसिक परेशानी व परिवाद खर्च के भी दिए जाएं। *(दै.भा., 10.08.22)*

'कट्स' के निदेशक चुने गए सीसीसी के उपाध्यक्ष

जयपुर स्थित 'कट्स' इंटरनेशनल के निदेशक जॉर्ज चेरियन 9 सितंबर 2022 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में हुए चुनाव के दौरान भारत की कन्ज्यूमर कोआर्डिनेशन कौंसिल (सीसीसी) के उपाध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। सीसीसी के संविधान के अनुसार, चुनाव दो साल में एक बार होता है और उपाध्यक्ष बनने के दो साल बाद स्वतः सीसीसी का अध्यक्ष बन जाता है।

भारत के 22 विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय उपभोक्ता सम्मेलन और सीसीसी की वार्षिक आम सभा की बैठक के दौरान चुनाव में भाग लिया। सीसीसी भारत के सभी उपभोक्ता संगठनों का सर्वोच्च उपभोक्ता निकाय है और भारत के उपभोक्ताओं की आवाज है, जिसकी स्थापना 1983 में भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के हितों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने के लिए की गई थी।

'कट्स' के निदेशक केंद्रीय सलाहकार समिति में शामिल

'कट्स' इंटरनेशनल के निदेशक जॉर्ज चेरियन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) की केंद्रीय सलाहकार समिति में तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनः शामिल किया गया है। जॉर्ज ने 1914 से 2019 के दौरान भी दो बार केंद्रीय सलाहकार समिति में 'कट्स' का प्रतिनिधित्व किया है। यह तीसरा अवसर है जब 'कट्स'को इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। वर्तमान में जॉर्ज खाद्य पदार्थों के पैकेट पर चेतावनी लेबल अभियान का भी नेतृत्व कर रहे हैं और 2021 से एफ.एस.एस.ए.आई के फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग के हितधारकों के समूह के सदस्य हैं।

उपभोक्ता न्याय से वंचित क्यों?

प्रदेश की उपभोक्ता अदालतों में लंबे समय से अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्तियां नहीं होने से पेंडिंग केसों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इन अदालतों में पेंडिंग केसों की संख्या 50 हजार से भी ज्यादा हो गई हैं। उपभोक्ता जल्द मिलने वाले न्याय से वंचित हो रहे हैं।

बावजूद इसके, राज्य सरकार ने उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों की जल्द नियुक्ति करने के बजाय 2021 में शुरू की कई नियुक्ति प्रक्रिया को ही बिना किसी कारण रद्द कर दिया। सवाल खड़ा होता है कि राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं के कानूनी अधिकारों की अनदेखी करते हुए पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को क्यों रद्द किया?

जबकि उपभोक्ता अदालतों के लिए सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है। हर साल वेलफेयर फंड के जरिए ही सरकार के पास करोड़ों रुपए आते हैं। कोर्ट फीस से भी लाखों रुपए का फंड सरकार को मिलता है *(दै.भा., 12.09.22)*

स्रोत: रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, स.ज.: समाचार जगत, रा.दू.: राष्ट्रदूत

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.228 2821
फैक्सः 228 2485, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org
यहां भी दिल्ली, कोलकता और चित्तौड़गढ़ (भारत); लुसाका (जाम्बिया); नैराबी (केन्या); आक्करा (घाना); हनोई (वियतनाम); जिनेवा (स्विटजरलैंड) और वॉशिंगटन डी.सी. (यूएसए)